Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

दिसंबर 2022 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- चिरंजीवी योजना में नि:शुल्क कॉकलियर इंप्लांट 3
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का किया शुभारंभ 4
- उद्योग मंत्री ने की 'मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोज़गार योजना' लॉन्च 4
- जयपुर में बनेगा प्रदेश का पहला स्वचालित रोप-वे 4
- ई-फाइलिंग लागू करने वाला प्रदेश का पहला कलक्ट्रेट बना जयपुर 5
- अलवर ज़िला कलक्टर को मिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ ज़िले का पुरस्कार 6
- राजस्थान आई.टी किक्रेट लीग का उद्घाटन 6
- राजीविका का इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक तथा फीनो पैमेंट बैंक के साथ एमओयू 7
- राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू 7
- राज्यपाल राहत कोष के लिये एस.बी.आई. ने निर्मित किया क्यूआर कोड 8
- पाली तहसील गंभीर सूखाग्रस्त घोषित 8
- उद्योग आयुक्त ने किया '56 भोग उत्सव- 2022' पोस्टर का विमोचन 9
- बीकानेर के लाखासर और हनुमानगढ़ के सतीपुरा में पोटाश के भंडार होने के संकेत मिले 9
- 'राजस्व निर्णय विशेषांक' का विमोचन 10
- हर साल पेश होगा पृथक कृषि बजट 10
- चार दिवसीय फूड फेस्टिवल '56 भोग उत्सव-2022' का शुभारंभ 11
- जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में योगसाधना भवन का लोकार्पण व संविधान पार्क और नवग्रह-नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास 11
- कोटा ज़िले में नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिये 120.80 करोड़ रुपए स्वीकृत 12
- राजस्थान आईटी क्रिकेट टूर्नामेंट-2022 12
- मुख्यमंत्री ने राजगढ़, लाडनू, पीपल्दा, सुल्तानपुर तथा चौथ का बरवाड़ा में स्टेडियम निर्माण की दी स्वीकृति 13
- राजस्थान के मुख्य न्यायाधिपति ने किया 'इंटीग्रेटेड साफ्टवेयर सोल्युशन विद ई-प्रिजन' प्रोग्राम को ई-लॉन्च 13
- 'द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स 2022- राजस्थान'का आयोजन 14
- सहकारिता मंत्री ने राज सहकार वेबसाइट का किया लोकार्पण 15
- उद्योग मंत्री ने किया हैंडलूम प्रदर्शनी का उद्घाटन 15
- राजस्थान 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) 2022' से सम्मानित 16
- खोले के हनुमान जी मंदिर 'रोप-वे' का लाइसेंस जारी 16
- सीएनजी गैस वितरण के लिये 1187 सीएनजी स्टेशन होंगे स्थापित 17
- राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन 18
- निर्भया फंड के लिये 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत 18
- 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' को मिला राष्ट्रीय स्तर का 'स्कॉच अवार्ड' 19
- राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिये मिला राष्ट्रीय पुरस्कार 19
- पुलिस आधुनिकीकरण योजना की क्रियान्विति एवं प्रगति की समीक्षा के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन 20
- मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के लिये 28.23 करोड़ रुपए की मंज़ूरी 20
- राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल-2023 के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ 20
- लोक संस्कृति के अनूठे पर्व 'शिल्पग्राम' उत्सव का हुआ आगाज 21
- जल जीवन मिशन के तहत 1055 करोड़ 99 लाख रुपए की 104 संशोधित लघु पेयजल योजनाओं (ओटीएमपी) को स्वीकृति 22
- महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किया राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ 22
- श्रीगंगानगर ज़िले में राज सखी कैफे का शुभारंभ 23
- बाड़मेर-जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गेल इंडिया करेगी खनिज तेल व प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन 23
- 16 राज्यमार्गों के निर्माण के लिये 4279.70 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी 24
- अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 24
- 'राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस' योजना के लिये 65 करोड़ रुपए मंज़ूर 25
- मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने राजस्थान डीआईपीआर को दिया इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्यूनिकेशन अवार्ड 25
- प्रदेश में 'स्टेट-ऑफ-द-आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर'तथा 'ओपन जिम'स्थापित करने के लिये 31 करोड़ 50 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान 26
- जोधपुर का कागल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत 26
- 10वाँ अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह 26
- खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपी अंतिम रिपोर्ट 27

नोट :

राजस्थान

चिरंजीवी योजना में नि:शुल्क कॉकलियर इंप्लांट

चर्चा में क्यों ?

30 नवंबर, 2022 को राजस्थान के जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ईएनटी विभाग के प्रोफेसर डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने बताया कि राज्य में 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत अब सरकारी अस्पताल में कॉकलियर इम्प्लांट पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- प्रोफेसर डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने बताया कि जन्म से सुनने और बोलने की अक्षमता एक गंभीर समस्या है, जिसका असर आजीवन रह सकता है। भारत में पैदा होने वाले प्रति एक हजार बच्चों में से चार बच्चे ऐसी विकृति के साथ पैदा होते हैं। इसके उपचार में कॉकलियर इम्प्लांट तकनीक बेहद कारगर सिद्ध हुई है। विशेष रूप से राजस्थान इस तकनीक के ज़रिये उपचार उपलब्ध करवाने में देश में अग्रणी राज्य बनकर सामने आया है।
- उन्होंने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट करने के लिये रोगी के मस्तिष्क में इस कॉकलियर नर्व का होना आवश्यक होता है। लेकिन जिन मरीजों में यह नर्व नहीं होती, उनमें सर्जरी के ज़रिये कॉकलियर नस विकसित कर इम्प्लांट किया जाता है, जिसे ऑडिटर ब्रेन स्टेम कहते हैं। यह अत्याधुनिक तकनीक है, जो अभी केवल चेन्नई व दिल्ली के कुछ निजी अस्पतालों में ही इस्तेमाल की जाती है।
- राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहाँ यह 18 से 20 लाख रुपए में होने वाला बेहद खर्चीला इम्प्लांट सरकारी अस्पताल में नि:शुल्क किया जा रहा है।
- ज्ञातव्य है कि राजस्थान आंध्र प्रदेश और केरल के बाद देश का तीसरा ऐसा राज्य है, जहाँ कॉकलियर इम्प्लांट के ज़रिये पाँच वर्ष तक के करीब एक हज़ार 100 बच्चों की सुनने और बोलने की क्षमता लौटाई जा रही है।
- गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश और केरल में जहाँ यह तकनीक निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध है, वहीं राजस्थान में यह मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध है।
- वर्तमान में प्रदेश के पाँच शहरों के राजकीय अस्पतालों में नि:शुल्क कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध है। इनमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर शहर शामिल हैं।
- जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अब तक 700, जयपुरिया अस्पताल में 95, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में 145, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में 40, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 60 तथा जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में 20 इम्प्लांट किये जा चुके हैं।
- प्रोफेसर डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट के लिये बच्चों की जितनी कम आयु होती है, उतना ही अधिक लाभ मिलता है। स्वास्थ्य नीति के अनुसार इम्प्लांट के लिये नौ महीने की आयु अनुमोदित है, यानी कम से कम नौ महीने से बड़े बच्चों का ही ऑपरेशन हो सकता है।
- राजस्थान में 4 साल से कम उम्र के बच्चे निशुल्क इलाज प्राप्त कर सकते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन सामान्यत: बहुत महंगा है। प्रत्येक ऑपरेशन का खर्च कम से कम आठ से 10 लाख होता है।
- विदित है कि 1 अप्रैल, 2022 से कॉकलियर इम्प्लांट को 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' में शामिल किया गया है।

नोट :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

30 नवंबर, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य के अलवर ज़िले के प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय 'ट्रांसजेंडर उत्सव'का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक सुरक्षा के लिये ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया है जिसमें 10 करोड़ रुपए का प्रावधान कर ट्रांसजेंडर्स समुदाय को इससे बड़ी राहत प्रदान की जा रही है।
- देश में राजस्थान संभवतया पहला राज्य है जिसमें इस प्रकार की योजना लागू हुई है।
- उन्होंने बताया कि राज्य में ट्रांसजेंडर्स के लिये शिक्षा, छात्रवृत्ति के साथ-साथ स्वरोज़गार की योजना लागू की गई है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, ट्रांसजेंडर्स को लिंग परिवर्तन सर्जरी व अन्य चिकित्सा सुविधा के लिये चिरंजीवी योजना से जोड़ा गया है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने 13 ट्रांसजेंडर्स को प्रतिकात्मक रूप से ट्रांसजेंडर आईडी भेंट की। इसके अलावा समारोह में विभिन्न स्थानों से आए हुए ट्रांसजेंडर्स को सक्षम अलवर अभियान का मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत किया।
- उन्होंने ट्रांसजेंडर्स की मांग पर अगला ट्रांसजेंडर उत्सव कोटा में मनाने की घोषणा भी की।

उद्योग मंत्री ने की 'मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोज़गार योजना' लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

1 दिसंबर 2022 को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्योग भवन स्थित बीआईपी बोर्ड रूम में 'मुख्यमंतरी लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोज़गार योजना' को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिये ज्यादा से ज्यादा स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु इस योजना को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के3300 व्यक्तियों को 'पहले आओ-पहले पाओ'के आधार पर लाभ दिया जाएगा।
- योजना के तहत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन (स्मॉल कमर्शियल व्हीकल) क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60 हज़ार (दोनों में से जो भी कम) का अनुदान राज्य सरकार से तथा समकक्ष/अधिक अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाएगा।
- उद्योग मंत्री ने बताया कि योजना के तहत कोई भी राजस्थान निवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य है, अपनी एसएसओ आईडी या mlvsy.rajasthan.gov.in के ज़रिये आवेदन कर सकता है।
- प्रस्तुत आवेदन ज़िला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा जाँच के बाद संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा। कंपनी द्वारा दस्तावेज़ अपलोड कर परीक्षण के लिये दोबारा ज़िला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों को भेजा जाएगा। वहाँ परीक्षण के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि योजना के लिये तीन वाहन कंपनियों-टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र बनाया गया है। टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 तथा महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट पर यह योजना लागू होगी।

जयपुर में बनेगा प्रदेश का पहला स्वचालित रोप-वे

चर्चा में क्यों ?

2 दिसंबर, 2022 को जयपुर कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जयपुर शहर में स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में बनने वाले प्रदेश के पहले स्वचालित और जयपुर के सबसे बड़े पेसेंजर रोप-वे निमार्ण का निरीक्षण किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जयपुर कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि इस रोप-वे का नाम अन्नपूर्णा माता रोप-वे होगा जो कि प्रदेश का पाँचवाँ और जयपुर ज़िले के सामोद हनुमानजी रोप-वे के बाद दूसरा रोप-वे होगा।
- अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णोमाता मंदिर तक 436 मीटर लंबा रोप-वे बनाया जा रहा है।
- रोप-वे निर्माण के लिये फर्म और जयपुर ज़िला प्रशासन के बीच करार हुआ है जिसके बाद फर्म को रोप-वे अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्माता फर्म को 2 साल में रोप-वे निर्माण के निर्देश दिये हैं।
- निरीक्षण के दौरान रोप-वे निर्माण की फर्म के पदाधिकारियों ने कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित को बताया कि पाँच टावरों पर संचालित किये जाने वाले रोप-वे की ऊँचाई 85 मीटर होगी। 24 ट्रॉली वाले इस रोप-वे की क्षमता 800 यात्री प्रति घंटा होगी।
- कलक्टर ने बताया कि निर्माण के दौरान और संचालन के शुरू होने के बाद भी ज़िला प्रशासन द्वारा रोप-वे के सुरक्षा मापदंडों की नियमित रूप से जाँच की जाएगी। रोप-वे के निर्माण में जयपुर की विरासत, शिल्पकला और वैभव की छटा देखने को मिलेगी।
- कलक्टर ने कहा कि रोप-वे निर्माण करने वाली फर्म को 0 से 5 आयुवर्ग वाले बच्चों और 70 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के साथ-साथ दिव्यांगों को रोप-वे के ज़रिये नि:शुल्क सफर करवाने के लिये निर्देशित किया गया है।
- रोप-वे के एक तरफ का सफर करीब साढ़े 4 मिनट में पूरा होगा इस दौरान यात्रियों को जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाने के लिये ट्रॉली को बीच सफर में दो बार रोका जाएगा।

ई-फाइलिंग लागू करने वाला प्रदेश का पहला कलक्ट्रेट बना जयपुर

चर्चा में क्यों ?

3 दिसंबर, 2022 को जयपुर कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जयपुर कलेक्ट्रेट में ई-फाइलिंग सिस्टम को लागू किया गया है। राजस्थान में ई-फाइलिंग लागू करने वाला जयपुर पहला कलेक्ट्रेट बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- जयपुर कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने एक नवाचार के तहत जयपुर कलेक्ट्रेट में ई-फाइलिंग सिस्टम को लागू किया है। कलेक्ट्रेट की संस्थापन शाखा और सामान्य शाखा से ई-फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। जल्द ही ई-फाइलिंग सिस्टम को पूरे कलेक्ट्रेट में लागू किया जाएगा।
- अतिरिक्त ज़िला कलक्टर (प्रथम) दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जयपुर ज़िला कलेक्ट्रेट को पेपरलैस बनाने की दिशा में ई-फाइलिंग सिस्टम मील का पत्थर साबित होगा। इस फैसले से न केवल कागज की बचत होगी बल्कि फाइलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना भी मुमकिन होगा।
- ज़िला कलेक्ट्रेट में अभी तक राज-कार्य कागज की पत्रावलियों के माध्यम से हो रहा था, जिससे न केवल बड़ी मात्रा में कागज की खपत हो रही थी, साथ ही इन पत्रावलियों और फाइलों का सुरक्षित संधारण सुनिश्चित करना मुश्किल होता था। अब राजस्थान सरकार के सूचना एवं तकनीकी विभाग द्वारा तैयार किये गए राज-काज सॉफ्टवेयर से सारा राज-कार्य ई-फाइलिंग सिस्टम के जरिये होगा।
- इसके तहत पत्रावली भौतिक न होकर ऑनलाइन प्रारूप में होगी। राज-काज सॉफ्टवेयर पर ही पत्रावली तैयार की जाएगी और ऑनलाइन ही संबंधित अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। अधिकारी अपनी एसएसओ आईडी से लॉगइन कर पत्रावली पर कार्यालय टिप्पणी कर सकेंगे या फिर डिजिटल साइन के माध्यम से फाइल का अनुमोदन कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन ही आदेश भी जारी हो सकेंगे।
- ई-फाइलिंग सिस्टम लागू होने से जयपुर कलेक्ट्रेट में कार्यालय टिप्पणी से लेकर पत्रावली अनुमोदन तक की सारी प्रक्रिया पेपर लैस हो जाएगी और फाइलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।
- फाइलों के फिजिकल मूवमेंट नहीं होने से पेपर, समय और मानव-श्रम की बचत तो होगी ही साथ ही वर्क फ्रॉम होम और वर्क ऐनी ह्वेयर, ऐनी टाइम की अवधारणा भी मुमकिन हो पाएगी। राजकीय कार्यों में सरलता और पारदर्शिता तो आएगी ही साथ ही पत्रावलियों का संचालन और संधारण पहले के मुकाबले और आसान हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के ज़िला कार्यालय में भी ई-फाइलिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है।

नोट :

अलवर ज़िला कलक्टर को मिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ ज़िले का पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

3 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में अलवर ज़िला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को वर्ष 2022 के लिये दिव्यांगजन सशक्तीकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ ज़िले का पुरस्कार प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान कैडर में अक्सर अपने नवाचारों के लिये चर्चित रहने वाले आईएएस अफसर और अलवर ज़िला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को यह अवार्ड ज़िले में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिये राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर एवं उनके कल्याण के लिये नवाचार करते हुए दिव्यांग सशक्तीकरण की दिशा में किये गए कार्यों के लिये दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिव्यांगजन के लिये सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश के केवल एक ज़िले को प्रदान किया जाता है।
- डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी से पहले साल 2022 में राजस्थान के 6 और आईएएस अफसरों को भी राष्ट्रीय स्तर पर अवॉर्ड मिल चुके हैं। राजस्थान कैडर में इस समय करीब 248 आईएएस अफसर हैं, जिनमें से करीब 10 अफसर तो ऐसे हैं, जिनको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के हाथों अवॉर्ड मिल चुके हैं।
- वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय (सीएमओ) में शासन सचिव के पद पर तैनात आईएएस गौरव गोयल को 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अवॉर्ड मिला था। यह अवॉर्ड 'स्क्रॉल ऑफ ऑनर' के नाम से दिया गया था। नोटबंदी के दौरान कैशलेस भुगतान को प्रमोट करने के लिये उनको यह अवॉर्ड दिया गया था।
- कोरोना में सरकारी स्कूलों से पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों में से करीब 90 प्रतिशत को वापस स्कूलों में नामांकित करने में मिली सफलता के लिये शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से नवंबर-2022 में अवॉर्ड मिला था।
- चूरू ज़िला के कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को ज़िले में खेलो इंडिया योजना को कामयाब बनाने और चूरू ज़िले के शानदार प्रदर्शन के लिये प्रधानमंत्री के स्तर पर 'नेशनल एक्सीलेंसी अवॉर्ड' दिया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है।
- सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा को सरकारी विभागों में सामान खरीदने की प्रक्रिया (पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस) को पारदर्शी बनाने के लिये केंद्र सरकार के अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से जून-2022 में राष्ट्रीय अवॉर्ड मिला था।
- वर्तमान में हनुमानगढ़ ज़िले की कलेक्टर रुक्मणि रियार को केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण मंत्रालय की ओर से नवंबर-2022 में ई-गवर्नेंस में बेस्ट वर्क के लिये अवॉर्ड दिया गया था।
- इनके अलावा वर्तमान में करौली के कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को इस साल 2 बार नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है। उनको मार्च-2022 में जल संरक्षण के लिये जल शक्ति मंत्रालय की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जुलाई-2022 में ज़िले में लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल अवॉर्ड दिया है।

राजस्थान आई.टी किक्रेट लीग का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

3 दिसंबर, 2022 को राजस्थान सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त आशीष गुप्ता द्वारा भवानी निकेतन क्रिकेट ग्राउंड्स में राजस्थान आई.टी किक्रेट लीग के तृतीय संस्करण का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- क्रिकेट लीग के मुख्य आयोजक ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस बार लीग में विभाग में विभिन्न ज़िलों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की 26 ज़िलों की टीमों सहित 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान आई.टी किक्रेट लीग का प्रथम संस्करण 2019 में एवं द्वितीय संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था।

नोट :

राजीविका का इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक तथा फीनो पैमेंट बैंक के साथ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2022 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) द्वारा मिशन 'वन जीपी -वन बीसी'प्रोजेक्ट के अंर्तगत राज्य के 17 ज़िलों में स्वयं सहायता समूहों की प्रशिक्षित एवं आईआईबीएफ सर्टिफाइड महिलाओं को बीसी सखी के रूप में लगाने हेतु इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक तथा फीनो पैमेंट बैंक के साथ एमओयू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इसके अतिरिक्त 25 नवंबर, 2022 को 'पे-नियर बाय'फिनटेक ऐजेंसी के साथ 8 ज़िलों में भी बीसी सखी लगाने हेतु एमओयू किया गया था। इस प्रकार अभी तक 25 ज़िलों में बीसी सखी लगाने के लिये एमओयू किया जा चुका है एवं अतिशीघ्र ही शेष 8 ज़िलों के लिये एयरटेल पेमेंट बैंक से एमओयू किया जाना है।
- इसके साथ ही 25 अगस्त, 2022 को राज्य स्तरीय महिला समानता दिवस आयोजन कार्यक्रम के अवसर पर 4825 बीसी सखी लगाए जाने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तथा आईडीएफसी बैंकों के साथ भी बीसी सखी लगाए जाने हेतु एमओयू किया जा चुका है।
- उल्लेखनीय है कि विभिन्न बैंकों के माध्यम से लगाई गई बीसी सखी संबंधित ग्राम पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों तथा स्वयं सहायता समूहों के परिवारों को नि:शुल्क बैंकिग सेवाएँ उपलब्ध करवा रही हैं। इससे उन्हें डोर स्टेप बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही इन बीसी सखियों की आमदनी का एक अच्छा जरिया बनने से उनका सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता तथा बैंकिंग कौशल में वृद्धि हो रही है।
- डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं में प्रमुख रूप से बचत खाता खोलना, रकम निकासी, रकम जमा करने के साथ-साथ बैंकिंग सेवाओं के अन्य प्रोडेक्टस जैसे बीमा एवं पेंशन योजनाओं में नामांकन की सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के साथ पेंशन वितरण, डीबीटी का पैसा निकासी की सुविधा शामिल हैं।

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2022 को राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये घोषित 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना'को लागू कर दिया गया है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गाँवों के जीवन, कला संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राज्य बजट में 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना'की घोषणा की थी।
- योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयाँ स्थापित होने से स्थानीय लोक कला को प्रोत्साहन और हस्तशिल्प का संरक्षण होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।
- 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना'के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को देय लाभ-
  - स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आरंभ में 25 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय होगी, पर्यटन इकाई शुरू होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जाएगा।
  - देय एवं जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा।
  - 'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

नोट :

- ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू-संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होगी।
- वन विभाग के अधीन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन का प्रोत्साहन राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- स्थानीय लोक कलाकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा ग्रामीण स्टार्टअप को अनुमोदन एवं देय लाभों में प्राथमिकता दी जाएगी।

- 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना'की विशेषताएँ-
  - ग्रामीण गेस्ट हाउस: ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस पंजीकृत किये जाएंगे, जिनमें 6-10 कमरे होंगे। ये कमरे पर्यटकों के ठहरने के लिये किराए पर उपलब्ध होंगे। गेस्ट हाउस में पर्यटकों के भोजन की व्यवस्था भी होगी।
  - कृषि पर्यटन इकाई: कृषि भूमि पर अनुमोदित पर्यटन इकाई न्यूनतम 2,000 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर पर स्थापित होगी। इसके 90 प्रतिशत हिस्से में कृषि और बागवानी कार्य, ऊँट फार्म, घोड़ा फार्म, पक्षी एवं पशुधन, फसल बोने के लिये, हस्तशिल्प, बगीचे आदि गतिविधियों के द्वारा पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश उपलब्ध करवाया जाएगा।
  - कैंपिंग साइट: कृषि भूमि पर न्यूनतम 1,000 वर्गमीटर एवं अधिकतम एक हेक्टेयर पर कैंपिंग साइट स्थापित हो सकेगी। इसके 10 प्रतिशत हिस्से पर टेंट में अस्थायी आवास की व्यवस्था होगी। शेष हिस्से में ऊँट फार्म, घोड़ा फार्म, पशुधन, बगीचे आदि गतिविधियाँ होंगी।
  - कैरावैन पार्क: कृषि भूमि पर न्यूनतम 1,000 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 1 हेक्टेयर पर कैरावैन पार्क स्थापित हो सकेगा। इस पर अतिथियों के वाहन पार्क किये जाने के बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा।
  - होम स्टे (पेईंग गेस्ट हाउस): पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व में जारी होम स्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू है। इसके तहत आवास मालिक द्वारा स्वयं के आवास में पर्यटकों को 5 कमरों तक आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरावैन पार्क का प्रोजेक्ट अनुमोदन और पंजीकरण पर्यटन विभाग के संबधित पर्यटक स्वागत केंद्र द्वारा किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण पर्यटन इकाइयों के लिये 15 फीट चौड़ी सड़क होना आवश्यक होगा।

राज्यपाल राहत कोष के लिये एस.बी.आई. ने निर्मित किया क्यूआर कोड

चर्चा में क्यों ?

6 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य में राज्यपाल राहत कोष के लिये निर्मित क्यूआर कोड का लोकार्पण किया। यह क्यूआर कोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल ने बताया कि 'डिजिटल भारत'के तहत यह एक महत्त्वपूर्ण पहल है तथा इस क्यूआर कोड के लोकार्पण से राज्यपाल राहत कोष के लिये अब क्यूआर कोड स्कैन कर सहयोग राशि सीधे बैंक खाते में जमा कराई जा सकेगी।
- उन्होंने बताया कि राज्यपाल राहत कोष का दायरा बढ़ाने और इससे अधिकाधिक रूप में ज़रूरतमंदों को हर संभव प्रभावी सहयोग किये जाने हेतु इसे शुरू किया गया है।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक धीरेंद्र कुमार दास ने बताया कि राज्यपाल राहत कोष के क्यूआर कोड निर्मित होने से पूर्णरूप से सुरक्षित रूप में लोग अब इसमें अपनी धनराशि ज़रूरतमंदों के सहयोग के लिये दान कर सकेंगे। यह राशि सीधे राज्यपाल राहत कोष के बैंक में स्थानांतरित हो जाएगी।

पाली तहसील गंभीर सूखाग्रस्त घोषित

चर्चा में क्यों ?

6 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के शासन सचिव पी. सी. किशन ने बताया कि राज्य द्वारा पाली ज़िले में सतही जल और भू-जल की उपलब्धता में कमी, वर्षा की कमी, फसलों की खराब स्थिति और रिमोट सेंसिंग से प्राप्त सूचनाओं को ध्यान में रखकर पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पी. सी. किशन ने बताया कि खरीफ फसल संवत् 2079 में प्रभावित क्षेत्रों का सूखा प्रबंध संहिता 2016 के आधार पर आकलन करके राजस्थान अफेक्टेड एरियाज(सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट 1952 के तहत पाली जिले की पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिनियम की धारा 5 से 10 के प्रावधान पाली ज़िले की पाली तहसील के सूखाग्रस्त ग्रामों में अधिसूचना के प्रकाशित होने से 6 माह तक लागू रहेंगे।

उद्योग आयुक्त ने किया '56 भोग उत्सव- 2022' पोस्टर का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

7 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के उद्योग आयुक्त महेंद्र पारख ने 9 से 12 दिसंबर तक जयपुर में स्थित जल महल के सामने राजस्थान हाट के अंतर्गत आयोजित होने वाले '56 भोग उत्सव-2022' के पोस्टर का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- महेंद्र पारख ने बताया कि '56 भोग उत्सव-2022' में राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन, प्रसिद्ध मसालों, मिठाइयों, नमकीन, विशिष्ट खाद्य पदार्थों एवं रसोई से जुड़े परंपरागत, प्राकृतिक एवं आधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे।
- उन्होंने बताया कि उत्सव में मनभावन व्यंजनों जैसे कि धौलपुर, भरतपुर एवं सीकर की गजक, पाली का गुलाब हलवा, गंगापुर का खीर मोहन, दौसा का डोवठा, अलवर का मावा, ब्यावर की तिलपपड़ी, बीकानेर की नमकीन, कोटा की कचौरी, जयपुर का घेवर, कुल्फी, तंदूरी चाय एवं पान आदि उपलब्ध होंगे।
- इसके अलावा राजस्थान के प्रसिद्ध साबुत एवं पिसे हुए मसालों, इनके पेस्ट एवं प्रोसेस्ड पैकेज के साथ-साथ परंपरागत पात्र, भरतपुर का आचार-मुरब्बे, सॉस, पापड़-बड़ी, खाखरे, पाचक चूर्ण, चटनी आदि के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे।
- उद्योग आयुक्त ने बताया कि इस हाट में राज्य की विशिष्ट सब्जियाँ जैसे कि बीकानेर की कैर-सांगरी, काचरी, अन्य सूखी परंपरागत सब्जियाँ, नागौरी मेथी, कोटा के मशरूम प्रोडक्टस् एवं खाद्य तेल खरीदने का जयपुर की जनता को सुनहरा अवसर मिलेगा।
- मेले में कबीरा ब्रांड खाद्य तेल, श्याम किचन मसाले एवं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने आयोजन की सहभागिता निभाई है। आयोजन के दौरान व्यंजन प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता, टॉक शो, क्वीज प्रतियोगिता एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।

बीकानेर के लाखासर और हनुमानगढ़ के सतीपुरा में पोटाश के भंडार होने के संकेत मिले

चर्चा में क्यों ?

8 दिसंबर, 2022 को राजस्थान माइंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के बीकानेर ज़िले के लाखासर और हनुमानगढ़ ज़िले के सतीपुरा में मात्र 500 से 700 मीटर गहराई पर ही पोटाश के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि दुनिया के पोटाश भंडार वाले देशों में पोटाश की उपलब्धता एक हज़ार मीटर या इससे भी अधिक गहराई में देखने को मिलती है।
- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के बीकानेर और हनुमानगढ़ में सिल्वाइट और पॉलिहाइलाइट पोटाश के संकेत मिलने से कंवेंसनल माइनिंग व सोल्यूशन माइनिंग तकनीक से पोटाश का खनन किया जा सकेगा।
- उन्होंने बताया कि बीकानेर के लाखासर के 99.99 वर्गमीटर क्षेत्र में 26 बोर किये गए हैं जिसमें से एमईसीएल द्वारा 22 बोर और जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 4 बोर किये गए हैं। इसमें दोनों ही तरह के यानी कि सिल्वाइट व पॉलिहाइलाइट पोटाश के संकेत मिले हैं।

नोट :

- इसके अलावा हनुमानगढ़ के सतीपुरा में भी जीएसआई द्वारा 300 वर्गमीटर क्षेत्र में किये गए एक्सप्लोरेशन में पोटाश के संकेत मिल चुके हैं।
- विदित है कि वर्तमान में देश पोटाश फर्टिलाइजर के लिये विदेशों से आयात पर निर्भर है जबकि प्रदेश में पोटाश के खनन की प्रक्रिया आंरभ होने से विदेशों से आयात की निर्भरता कम हो जाएगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
- एमईसीएल के सीएमडी घनश्याम शर्मा ने रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि सिल्वाइट पोटाश में सोल्यूशन माइनिंग की आवश्यकता होती है जबकि पॉलिहाइलाइट पोटाश में पंरपरागत तरीके से माइनिंग की जा सकती है तथा प्रदेश में दोनों ही तरह की माइनिंग की संभावनाएँ उभरकर सामने आई है।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में पोटाश के एक्सप्लोरेशन का संकेत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता कदम है। राजस्थान में पोटाश खनन से देश में अब खेती के लिये पोटाश फर्टिलाइजर की आवश्यकता को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।

'राजस्व निर्णय विशेषांक' का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

8 दिसंबर, 2022 को राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने राविरा पत्रिका के 'राजस्व निर्णय विशेषांक'का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्व मंडल की ओर से प्रकाशित 'राजस्व निर्णय विशेषांक'में राजस्व न्यायालयों में विधिसम्मत, गुणवत्तापूर्ण एवं त्रुटिरहित निर्णय पारित करने को लेकर महत्त्वपूर्ण आलेख, राज्य के राजस्व मंडल व अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर से पारित श्रेष्ठ निर्णयों एवं राज्य स्तर पर आयोजित राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली सुधार हेतु सुझाव विषयक पंचवर्गीय निबंध लेखन प्रतियोगिता के तहत चयनित श्रेष्ठ प्रविष्टियों को शामिल किया गया है।
- इसके अलावा राजस्व प्रशासन से जुड़े विषय विशेषज्ञों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे गए आलेख, सरकार द्वारा जारी महत्त्वपूर्ण परिपत्र, अधिसूचनाओं को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है।

हर साल पेश होगा पृथक कृषि बजट

चर्चा में क्यों ?

9 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघों के पदाधिकारियों तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि प्रति वर्ष कृषि के लिये अलग से बजट प्रस्तुत किया जाएगा ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन एवं इससे जुड़े क्षेत्र राज्य की जीडीपी एवं अर्थव्यवस्था की धुरी है। राज्य सरकार इस बार के बजट के माध्यम से प्रदेश के किसानों तथा पशुपालकों की समृद्धि एवं खुशहाली के लिये आवश्यक प्रावधान करने के लिये पूरी तरह प्रयासरत है।
- राज्य सरकार ने पहली बार अलग से कृषि बजट लाने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। राज्य सरकार सभी उपयोगी सुझावों को कृषि बजट में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेगी।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश की करीब दो-तिहाई आबादी विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं पानी की कमी के बावजूद अपनी मेहनत से कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को हमेशा अग्रणी पायदान पर रखने का सार्थक प्रयास करती है। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि बजट में ऐसे प्रावधान करें, जिससे राज्य के किसानों तथा पशुपालकों की आय बढ़े और वे खुशहाल हों।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषकों के कल्याण के लिये विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, कृषक कल्याण कोष का गठन, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ऋण माफी, सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जैसे कई अहम फैसले लिये गए हैं, जो कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। राजस्थान में तकनीक और नवाचारों के माध्यम से कृषि और डेयरी क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सकता है।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के किसान नवीन तकनीकों और नवाचारों को अपनाकर उन्नत कृषि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लायी गई बूंद-बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार ने खेतों में सोलर पैनल लगाकर किसानों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना लागू की है।

चार दिवसीय फूड फेस्टिवल '56 भोग उत्सव- 2022' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

9 दिसंबर, 2022 को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने राजस्थान हाट (जल महल) में चार दिवसीय फूड फेस्टिवल '56 भोग उत्सव- 2022' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योग विभाग व उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की ओर से आयोजित यह आयोजन प्रदेश के उत्पादों की छवि को निखारने का महत्त्वपूर्ण कार्य करेगा।
- उत्सव में राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन, प्रसिद्ध मसालों, मिठाइयों, नमकीन, विशिष्ट खाद्य पदार्थों एवं रसोई से जुड़े परंपरागत, प्राकृतिक एवं आधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे।
- उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश भर के व्यजनों, मसालों की उत्कृष्टता एवं क्षेत्रीय विविधता से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रूबरू करवाने के लिये यह विशेष आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य ज़िलों में चल रहे व्यंजनों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना और उनकी ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना है।
- राजस्थान के उद्योग आयुक्त महेंद्र पारख ने बताया कि प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों से बेहतरीन व्यजनों को चयनित कर आगंतुकों के लिये प्रदर्शित किया जा रहा है। विभाग द्वारा ऐसे फूड फेस्टिवल प्रति वर्ष लगाने की योजना है, ताकि लोगों को स्तरीय जायके के साथ उत्पादकों को बेहतर ग्राहक मिल सके।
- उन्होंने बताया कि आयोजन के दौरान व्यंजन प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता, टॉक शो, क्वीज प्रतियोगिता एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में आईएएस केके पाठक के नेतृत्व में 'रसोई-2019' फूड फेस्टिवल का आगाज उद्योग विभाग द्वारा किया गया था, जो कि काफी सफल और लोकप्रिय भी रहा था।

जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में योगसाधना भवन का लोकार्पण व संविधान पार्क और नवग्रह-नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

10 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने जयपुर स्थित जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में शिलापट्टिकाओं का अनावरण कर योगसाधना भवन का लोकार्पण और संविधान पार्क एवं वैज्ञानिक आधार पर तैयार करवाई जा रही नवग्रह-नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल कलराज मिश्र ने नई पीढ़ी को आधुनिक जीवन शैली से जुड़े दुष्प्रभावों से बचाने के लिये यौगिक दिनचर्या से जोड़ने का आह्वान किया है और बताया कि योग आत्मविकास का सबसे बड़ा माध्यम है, भौतिकता के दौर में मानसिक शांति एवं संतोष के लिये योग सर्वथा उपयोगी है।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान आने के बाद प्रदेश के सभी वित्त-पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क स्थापित करवाना उनकी प्राथमिकता रही है, ताकि भावी नागरिक संविधान प्रदत्त जीवन मूल्यों से जुड़े और अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उन्हें भान रहे।

नोट :

- उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में नवनिर्मित योग साधना भवन को योग के शास्त्रीय अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ योग से जुड़े शास्त्रों और योग की महान धरोहर से जुड़े आधुनिक ज्ञान को संस्कृत से अनुदित कर हिन्दी और दूसरी भाषाओं में उपलब्ध किया जा सके।
- विश्वविद्यालय में बनने जा रही नवग्रह-नक्षत्र वाटिका ज्योतिष से जुड़े पौराणिक शोध और निष्कर्षों को सहज रूप में व्याख्यायित करेगी और पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति से भी विद्यार्थियों को जोड़ेगी।
- इस अवसर पर राज्यपाल ने नवग्रह-नक्षत्र वाटिका की पुस्तक का लोकार्पण भी किया।
- संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने बताया कि विश्व में भारत देश की प्रतिष्ठा संस्कृत भाषा और हमारी संस्कृति के कारण ही है तथा राजस्थान में संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिये राज्य सरकार व्यापक स्तर पर प्रयास कर रही है।

कोटा ज़िले में नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिये 120.80 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

11 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कोटा ज़िले में प्रस्तावित नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिये 80 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्षेत्र में ई.एच.वी. पावर लाइनों को शिफ्ट करवाने हेतु लगभग 40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है।
- प्रस्ताव के अनुसार, कोटा में नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिये 80 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं, जिसमें से 45 करोड़ रुपए नगर विकास न्यास कोटा तथा शेष 75.80 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाएंगे।
- इसके अलावा, एयरपोर्ट क्षेत्र में आ रही ई.एच.वी. पावर लाइनों को शिफ्ट करने का कार्य पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस कार्य के लिये लगभग 40 करोड़ रुपए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के आरओई से व्यय किये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से शैक्षणिक एवं औद्योगिक नगरी के रूप में कोटा का अंतर्राज्यीय हवाई मार्ग से संपर्क हो सकेगा।

राजस्थान आईटी क्रिकेट टूर्नामेंट-2022

चर्चा में क्यों ?

11 दिसंबर, 2022 को राजस्थान आईटी क्रिकेट टूर्नामेंट के तृतीय संस्करण का फाइनल मैच जयपुर के स्थानीय भवानी निकेतन ग्राउंड में आयोजित हुआ, जिसमें आईटी डेविल्स (यशपाल लॉयंस) ने जोधपुर रॉयल्स के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर जीत हासिल की।

प्रमुख बिंदु

- विजेता टीम को सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त सचिव एवं तकनीकी निदेशक सुनील छाबरा द्वारा आईटी कप से सम्मानित किया गया।
- क्रिकेट लीग के मुख्य आयोजक रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि लीग का उद्घाटन 3 दिसंबर को सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त आशीष गुप्ता द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता में विभिन्न ज़िलों की 26 टीमों ने भाग लिया, जिसके अंतर्गत 400 खिलाड़ियों द्वारा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया।
- फाइनल मैच में आईटी डेविल्स के कप्तान देवर्षि शर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया।

नोट :

मुख्यमंत्री ने राजगढ़, लाडनू, पीपल्दा, सुल्तानपुर तथा चौथ का बरवाड़ा में स्टेडियम निर्माण की दी स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

13 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत प्रदेश के राजगढ़, लाडनू, पीपल्दा, सुल्तानपुर तथा चौथ का बरवाड़ा में स्टेडियम निर्माण के लिये राज्यांश के रूप में 1 करोड़ 85 लाख रुपए प्रदान करने की मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, राजगढ़ (चुरू) में स्टेडियम निर्माण के लिये 1 करोड़ रुपए, लाडनू (नागौर), पीपल्दा एवं सुल्तानपुर (कोटा) में स्टेडियम निर्माण के लिये 25-25 लाख रुपए तथा चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) में स्टेडियम निर्माण के लिये 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
- स्टेडियम निर्माण से प्रदेश के खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के लिये स्थानीय स्तर पर ही बेहतर खेल सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में 'मेजर ध्यानचंद योजना' के तहत ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई थी।
- इस योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम निर्माण के लिये सांसद अथवा विधायक निधि, जनप्रतिनिधि, जन सहयोग, स्थानीय निकाय या सीएसआर फंड से प्राप्त राशि के बराबर अंशदान राशि राज्यांश के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

राजस्थान के मुख्य न्यायाधिपति ने किया 'इंटीग्रेटेड साफ्टवेयर सोल्युशन विद ई-प्रिजन' प्रोग्राम को ई-लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

13 दिसंबर, 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर बेंच के सभागार में राज्य के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल ने 'इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सोल्युशन विद ई-प्रिजन'प्रोग्राम को ई-लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल ने बताया कि 'इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सोल्युशन विद ई-प्रिजन' से न्यायालय के प्रकरणों से जुड़े विचाराधीन बंदियों की सभी सूचना जेल प्रशासन के ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर से प्राप्त की जा सकेगी।
- स्टियरिंग कमेटी के अध्यक्ष न्यायाधीश अरूण भंसाली के मार्गदर्शन में राजस्थान उच्च न्यायालय की तकनीकी टीम ने अल्प अवधि में ही उच्च न्यायालय एवं ज़िला न्यायपालिका के समस्त न्यायालयों के लिये इस प्रोग्राम का निर्माण किया है।
- राज्य की विभिन्न जेलों में निरूद्ध बंदियों के लिये बनाए गए ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को न्यायालय में चल रहे केस इन्फोरमेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करते हुए यह प्रोग्राम बनाया गया है।
- कार्यक्रम में न्यायाधीश ने राज्य के समस्त न्यायिक अधिकारियों को विचाराधीन बंदियों के रिमांड व विचारण में उनकी उपस्थिति अधिक से अधिक विडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से करवाने और ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की भी अपील की है।
- ई-लॉंचिंग कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि ऐसा करने वाला राजस्थान उच्च न्यायालय पूरे देश का प्रथम उच्च न्यायालय बन गया है। कोविड-19 महामारी के समय से ही कम्प्यूटराईजेशन, डिजीटलाईजेशन, ई-फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट व वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में तकनीकी क्रांति आई है।
- कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश संदीप मेहता ने बताया कि इस प्रोग्राम के माध्यम से किसी भी मुकदमे में यदि कोई अभियुक्त जेल में न्यायिक अभिरक्षा भुगत रहा है तो न्यायालय को उसकी समस्त जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। ये जानकारी उस मामले के न्यायपूर्ण एवं शीघ्र विनिश्चय के लिये काफी उपयोगी साबित होगी।
- इसके अलावा जेल में अभिरक्षारत अभियुक्त को भी अपने मामले की प्रगति के बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी, जो कि उसका संवैधानिक अधिकार भी है।

नोट :

'द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स 2022- राजस्थान'का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने वाले उद्यमियों को पुरस्कृत करने के लिये पर्यटन विभाग द्वारा क्लार्क्स आमेर होटल में 'द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स 2022-राजस्थान'का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले प्रतिभागियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिये गए। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, पर्यटन विभाग की निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा, पर्यटन मंत्रालय के उत्तरी क्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर अनिल ओरवा, होटल क्लार्क आमेर के प्रबंध निर्देशक अपूर्व कुमार और आउटलुक के सीईओ के इंद्रनील राय ने ये पुरस्कार प्रदान किये।
- पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने इस अवसर पर कहा कि यह अवार्ड समारोह साधारण से असाधारण बनने की दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- प्रमुख सचिव ने कहा कि 'द इंडियन टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022' उन लोगों को दिया गया है जो पर्यटन क्षेत्र में ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान समारोह आने वाले समय में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिये रोल मॉडल बनेगा।
- उन्होंने कहा पर्यटन विभाग का प्रयास है कि राज्य सरकार की टूरिज्म पॉलिसी के जरिये डूंगरपुर और बाँसवाड़ा जैसे आदिवासी व जनजाति क्षेत्रों में भी पर्यटको की आवाजाही बढ़े और वहाँ के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले।
- प्रमुख सचिव ने बताया कि राजस्थान पर्यटन विभाग राज्य की अर्थव्यवस्था में 13% का योगदान देता है और नई टूरिज्म पॉलिसी के ज़रिये इसे और आगे बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- आउटलुक के इंद्रनील रॉय ने कहा कि उनकी संस्थान की ओर से यह अवार्ड पिछले 8 वर्षों से दिये जा रहे हैं। राजस्थान में इस तरह का प्रथम आयोजन किया गया।
- कार्यक्रम में सस्टेनेबल लीडरशिप- होटल्स, सस्टेनेबल लीडरशिप- होमस्टे, सस्टेनेबल इंटरप्राइजेज इन ईको फ्रेंजाइल लेंडस्कैप, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन इन पाथफाइंडर एंड ग्रासरूट हीरोज, हेरिटेज कंजर्वेशन और वाइल्ड लाईफ कंजर्वेशन की श्रेणियों में पुरस्कार दिये गए।

विभिन्न श्रेणियों के विजेता हैं-

- सस्टेनेबल लीडरशिप- होमस्टे
  1. गोल्ड : रैप्टर इन
  2. सिल्वर : रावला बीसलपुर
  3. स्पेशल मेंशन : कंट्री रिट्रीट
- सस्टेनेबल लीडरशिप : होटल
  1. गोल्ड : ताज अरावली
  2. स्पेशल मेंशन : अमन-ए-खास
- इको-फ्रेंजाइल लैंडस्केप्स में सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज
  1. गोल्ड : वैदिक वॉक
  2. सिल्वर : विरासत एक्सपीरियंस
- हेरिटेज कंजर्वेशन
  1. ओवरऑल + गोल्ड विनर : कंकड़वा हवेली, उदयपुर
  2. सिल्वर अवॉर्डी : इंद्र विलास, अलसीसर
  3. स्पेशल मेंशन : राम कृष्ण मिशन, खेतड़ी

नोट :

- वाइल्ड लाईफ कंर्जवेशन
  1. सिल्वर : जगनाथ वाइल्डलाइफ सफारी, जालौर- रवींद्र सिंह- एशियाटिक वाइल्ड कैट
- सस्टेनेबिलिटी चैंपियन इन ग्रासरूट हीरोज
  1. सिल्वर : अनिरुद्ध शुक्ल - वैदिक वाक्
  2. सिल्वर : डॉ. राव अजीत सिंह
  3. स्पेशल मेंशन : ब्रिगेडियर नंदलाल वर्मा
- सस्टेनेबिलिटी चैंपियन इन पाथफाइंडर
  1. गोल्ड : मानवेंद्र सिंह शेखावत
  2. सिल्वर : संजय कौशिक
  3. स्पेशल मेंशन : दौलत सिंह शक्तावत

सहकारिता मंत्री ने राज सहकार वेबसाइट का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने सहकार भवन में सहकारिता विभाग की वेबसाइट https:@@rajsahakar.rajasthan.gov.in का लोकार्पण किया। राज सहकार वेबसाइट को आमजन की सुविधा के लिये नए तरीके से बनाकर सहकारिता से संबंधित सूचनाओं को व्यापक रूप दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सहकारिता की नई वेबसाइट के माध्यम से विभागीय सूचनाओं को सरल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न सोसायटियों/संस्था पंजीकरण, क्रेडिट सोसायटियों से संबंधित शिकायतों का रजिस्ट्रेशन भी सुलभ तरीके से किया जा सकता है।
- प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि आम नागरिकों को योजनाओं के बारे में सरल तरीके से जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर शीर्ष संस्थाओं की योजनाओं, विभागीय अधिकारियों का डेटाबेस, लोक सूचना अधिकारियों की सूचना, नियम, अधिनियम एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों को भी उपलब्ध कराया गया है।
- रजिस्ट्रार, सहकारिता मेघराज सिंह रतनू ने कहा कि विभाग की उपलब्धियाँ एवं सूचनाएँ भी इस वेबसाइट पर आसानी से मिल सकेगी तथा कोई भी नागरिक ई-मेल के माध्यम से सहकारिता से संबंधित अपने प्रश्नों को भी भेज कर जानकारी ले सकेगा।

उद्योग मंत्री ने किया हैंडलूम प्रदर्शनी का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हथकरघा भवन, चौमू हाउस, सी-स्कीम स्थित परिसर में पाँच दिवसीय हैंडलूम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की सीएमडी डॉ. मनीषा अरोड़ा ने बताया कि राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्त्र उद्योग को समुचित विपणन प्रोत्साहन देने के लिये 14 से 18 दिसंबर तक इस पाँच दिवसीय हैंडलूम प्रदर्शनी-कम सेल का आयोजन किया जा रहा है।
- प्रदर्शनी में प्रदेश के नेशनल अवार्डी एवं उत्कृष्ट बुनकरों तथा दस्तकारों द्वारा तैयार किये गए विभिन्न किस्मों के वस्त्र यथा डिजाइनर कोटा डोरिया, जरी, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड एवं सिल्क साड़ियाँ, ड्रेस मैटेरियल, सांगानेरी, बगरू प्रिंटेड बेडशीट्स, बाड़मेरी अजरख बेडशीट्स, कलात्मक दोहर, जयपुरी रजाई, दरियाँ, फैशनेबल कुर्ते, प्लाजो, शर्ट्स आदि उत्पाद बिक्री एवं प्रदर्शन के लिये रखे जाएंगे।
- इसके साथ ही राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. (राजस्थली) के आकर्षक हैंडीक्राफ्ट उत्पाद भी प्रदर्शन एवं बिक्री के लिये रखे जा रहे हैं। बुनकर सेवा केंद्र द्वारा हस्तचालित लूम पर डोरिया साड़ी वीविंग का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है।

नोट :

- इस अवसर पर राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने आमजन से हैंडलूम उत्पादों और परिधानों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपनों (स्थानीय कारीगरों) द्वारा अपनों (प्रदेशवासियों) के लिये बनाए उत्पादों के इस्तेमाल से पारंपरिक हस्तकलाओं को बचाया जा सकेगा।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प के उत्थान के लिये हाल में हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लागू की गई है, जिसका लाभ आर्टिजंस को मिलने लगेगा। दस्तकारों द्वारा शुद्ध प्राकृतिक रंगों और धागों के ज़रिये वस्त्र बनाए जा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदेमंद हैं।
- राजसिको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि राजस्थानी परिधान प्रदेशवासियों की पहचान है। जोधपुर में होने वाले इंटरनेशनल एक्सपो में हैंडलूम और टेक्सटाइल के उत्पादों का पवेलियन बनाया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि हैंडलूम के ज्यादा से ज्यादा उत्पादों की भी जीआई टैगिंग करवाई जा रही है, ताकि कला का संर्वधन और संरक्षण किया जा सके। उन्होंने बताया कि एक ज़िला-एक उत्पाद मिशन से आने वाले दिनों में निर्यात को खास बल मिलेगा।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक कलाओं के उत्थान के लिये हमेशा प्रयासरत रही है। इसी के मद्देनज़र सरकार द्वारा हैंडिक्राफ्ट पॉलिसी लाई गई है। इसके तहत हैडिक्राफ्ट और हैंडलूम निदेशालय स्थापित किये जा रहे हैं। इसका उद्देश्य कलाओं से जुड़े आर्टिजंस को प्रोत्साहित और कला का संरक्षण करना है।

राजस्थान 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) 2022' से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा की बचत के लिये उपलब्ध संसाधनों का दक्ष उपयोग करने के लिये राजस्थान को 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022' के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय) द्वारा 'सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट'प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित समारोह में यह पुरस्कार राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल ढाका को प्रदान किया।
- इस अवसर पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष आशुतोष ए. टी. पेडणेकर ने कहा कि यह पुरस्कार भारत-सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष उद्योग, भवन, म्यूनिसिपल, यातायात, कृषि, विद्युत प्रसारण तथा क्रॉस सेक्टर क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिये किये गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी की स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी/एजेंसीज को प्रदान किया जाता है।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल ढाका ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व तथा ऊर्जा राज्य मंत्री भँवर सिंह भाटी की ऊर्जा संरक्षण के प्रति विशिष्ठ संवेदना के कारण राज्य को गत वर्ष के साथ-साथ इस वर्ष भी 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) 2022' से नवाज़ा गया है।

खोले के हनुमान जी मंदिर 'रोप-वे' का लाइसेंस जारी

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को जयपुर ज़िला प्रशासन द्वारा खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश के पहले स्वचालित 'रोप-वे'निर्माण के लिये फर्म को रोप-वे अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

- लाइसेंस जारी होने से 85 मीटर ऊँचाई वाले प्रदेश के पहले स्वचालित रोप-वे के निर्माण कार्यों में तेजी आएगी तथा जल्द ही अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णों माता मंदिर तक पैसेंजर रोप-वे की सौगात यात्रियों को मिल सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि जयपुर कलक्टर की पहल पर शहर के खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पेसेंजर रोप-वे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
- रोप-वे का नाम अन्नपूर्णा माता रोप-वे होगा जो कि प्रदेश का पाँचवां और जयपुर ज़िले का सामोद हनुमानजी रोप-वे के बाद दूसरा रोप-वे होगा।

नोट :

- अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णोमाता मंदिर तक 436 मीटर लंबा रोप-वे बनाया जा रहा है जो कि जयपुर का सबसे बड़ा रोप वे होगा।
- रोप-वे निर्माण के लिये फर्म और जयपुर ज़िला प्रशासन के बीच करार हुआ है जिसके बाद फर्म को रोप-वे अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- पाँच टावरों पर संचालित किये जाने वाले रोपवे की ऊँचाई 85 मीटर होगी। 24 ट्रॉली वाले इस रोप वे की क्षमता 800 यात्री प्रति घंटा होगी। कलेक्टर ने निर्माता फर्म को 2 साल में रोप-वे निर्माण के निर्देश दिये हैं।
- कलक्टर ने कहा कि निर्माण के दौरान और संचालन के शुरू होने के बाद भी ज़िला प्रशासन द्वारा रोप वे के सुरक्षा मापदंडों की नियमित रूप से जाँच की जाएगी। रोप-वे के निर्माण में जयपुर की विरासत, शिल्पकला और वैभव की छटा देखने को मिलेगी।
- कलक्टर ने कहा कि रोप-वे निर्माण करने वाली फर्म को 0 से 5 आयुवर्ग वाले बच्चों और 70 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के साथ साथ दिव्यांगों को रोपवे के जरिये नि:शुल्क सफर करवाने के लिये निर्देशित किया गया है। रोप-वे की एक तरफ का सफर करीब साढ़े 4 मिनट में पूरा होगा इस दौरान यात्रियों को जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाने के लिये ट्रॉली को बीच सफर में दो बार रोका जाएगा।

सीएनजी गैस वितरण के लिये 1187 सीएनजी स्टेशन होंगे स्थापित

चर्चा में क्यों ?

15 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस व पेट्रोलियम, डॉ. सुबोध अग्रवाल ने राज्य में कार्यरत सभी 14 संस्थाओं के प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक में बताया कि सीएनजी गैस वितरण के लिये 1187 स्टेशन स्थापित किये जाएंगे, वहीं 37824 इंच किमी. पाईपलाइन बिछाई जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बैठक में बताया कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 8 साल में 96 लाख पाईपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जाएंगे।
- उन्होंने राज्य की 33 ज़िलों में कार्यरत 14 गैस कंपनियों को तय समय सीमा में पाईपलाइन से गैस वितरण व्यवस्था और सीएनजी वितरण व्यवस्था को प्रभावी करने के निर्देश दिये।
- उन्होंने बताया कि जयपुर के कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर और महेंद्र सेज में 10 हजार कनेक्शन मार्च 2023 तक जारी कर दिये जाएंगे।
- एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में इस समय पाईपलाइन से एक लाख 877 घरेलू गैस कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। वहीं 221 सीएनजी स्टेशन की स्थापना के साथ ही 7767 इंच किमी. पाईपलाइन बिछाने का काम हो चुका है।
- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, भरतपुर, सिरोही, जालौर, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, जयपुर, धौलपुर, कोटा, रावतभाटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर, पाली, जयसमंद में कार्य आरंभ हो चुका है।
- एमडी आरएसजीएल रणवीर सिंह ने बताया कि राज्य में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में एजएपी, अलवर (भिवाड़ी को छोड़कर), जयपुर (कोटा शहर को छोड़कर) बारां और चित्तौड़गढ़ (केवल रावतभाटा) में टोरेंट, भीलवाड़ा, बूंदी, रावतभाटा को छोड़कर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ में अडानी गैस, धौलपुर में एस्सेल, अजमेर, पाली, राजसमंद में इंद्रप्रस्थ गैस, जालौर, सिरोही, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, में गुजरात गैस, कोटा में राजस्थान गैस, भरतपुर में गैल गैस, भिवाड़ी में हरियाणा गैस, बीकानेर, चुरु, में दिनेश इंजीनियरिंग, झुंझुनूं, सीकर, नागौर में इंडियन ऑयल, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर व टोंक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, गंगानगर व हनुमानगढ़ में भारत पेट्रोलियम, झालावाड़ में मेघा इंजीनियिरंग द्वारा आधारभूत संरचना, व पाईप लाइन से गैस वितरण और सीएनजी का कार्य किया जा रहा है।

नोट :

राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

17 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 25 विभागों की सभी स्टॉल्स पर जाकर विभागों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों का अवलोकन किया तथा सभी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के बारे में अधिक-से-अधिक जागरूकता फैलाकर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के निर्देश दिये।
- उन्होंने 'सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म'का संदेश देती विकास प्रदर्शनी में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में करवाए गए विकास कार्यों एवं योजनाओं के फोटो, स्केच, मॉडल्स एवं प्रकाशन सहित अन्य सामग्री के बारे में बताया।
- इस विकास प्रदर्शनी में उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सुजस ऐप, सुजस बुलेटिन, सुजस ई-बुलेटिन एवं सुजस पॉडकास्ट 'आवाज़'का लोकार्पण भी किया।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के लिये लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश में एक जवाबदेह और पारदर्शी सुशासन स्थापित करने का कार्य भी किया गया है। 'इंदिरा रसोई योजना' में आमजन को पौष्टिक भोजन 8 रुपए में सम्मान के साथ परोसा जा रहा है।
- प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिये 800 करोड़ रुपए की 'उड़ान योजना'के माध्यम से नि:शुल्क सैनेटरी नेपकिन का वितरण किया जा रहा है।
- सरकार की योजनाओं से वर्तमान में प्रदेश में 46 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का बिजली बिल शून्य आ रहा है। 'इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना' के माध्यम से शहरी क्षेत्र के बेरोज़गारों को राहत दी जा रही है।
- उन्होंने बताया कि आमजन को महँगे उपचार से मुक्ति दिलाने के लिये 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' लागू की गई है। इसमें 10 लाख रुपए तक का नि:शुल्क उपचार मिल रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख की सीमा समाप्त कर सारा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके अलावा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।
- प्रदेश सरकार द्वारा आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार नि:शुल्क कर दिये गए हैं। प्रदेश में आमजन की सीटी स्केन, एम.आर.आई. स्केन जैसी महँगी जाँचें नि:शुल्क की जा रही हैं। इन ऐतिहासिक निर्णयों से राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है।
- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू किया, जिसमें वित्तीय प्रबंधन बेहतरीन रहा है, जिससे प्रदेश में सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है।
- राज्य के 13 ज़िलों में आमजन और किसानों के लिये 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)' अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि गत बजट में राज्य सरकार द्वारा ईआरसीपी के लिये 9600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा न मिलने तक राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इसे आगे बढ़ाएगी।

निर्भया फंड के लिये 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

19 दिसंबर, 2022 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रदेश में चल रहे 45 पोक्सो न्यायालयों हेतु निर्भया फंड में 60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंज़ूरी दी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अत्यंत संवेदनशील है तथा महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में निर्भया फंड मं अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंज़ूरी प्रदान की गई है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मिशन (फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट) निर्भया फंड के अंतर्गत प्रदेश में 45 पोक्सो न्यायालय संचालित हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत की फंडिंग की जाती है।
- इस फंड हेतु गहलोत सरकार ने 40.27 करोड़ रुपए राज्यनिधि मद में एवं 19.73 करोड़ रुपए केंद्रीयांश मद में अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंज़ूरी दी है, जिससे इन पोक्सो न्यायालयों में पदस्थापित कर्मचारियों/अधिकारियों के आगामी माह के संवेतन का निर्बाध आहरण हो सकेगा।

'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' को मिला राष्ट्रीय स्तर का 'स्कॉच अवार्ड'

चर्चा में क्यों ?

19 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हेबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में राजस्थान में गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से चलाई जा रही 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- पुरस्कार वितरण समारोह में इस योजना को द्वितीय पुरस्कार (सिल्वर मेडल) दिया गया। समेकित बाल विकास सेवाओं के निदेशक रामावतार मीणा एवं योजना में तकनीकी सहयोग दे रही संस्था आईपीई ग्लोबल की प्रतिनिधि दिव्या संथानम ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 5 जनजातीय ज़िलों बाराँ, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में इस योजना को शुरू किया गया था, जिसे वर्ष 2022-23 में राज्य के सभी 33 ज़िलों में लागू कर दिया गया है।
- इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर गर्भवती महिला को छह हज़ार रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरी तरह से पेपरलेस योजना है जिसमें लाभार्थी को किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं करना पडता, उसे स्वास्थ्य विभाग में दर्ज डाटा के आधार पर आनलाईन भुगतान किया जाता है। योजना के अंतर्गत लगभग 3.30 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिये मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

19 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में किये गए डिजिटल नवाचारों और संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला स्कोच पुरस्कार मिला।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार के जनकल्याण पोर्टल और ई-मित्र को ई-गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। जनकल्याण पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों और ज़िलों की वेबसाइट्स का निर्माण किया जाता है, जिससे राज्य सरकार से संबंधित सभी जानकारियाँ आमजन को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके।
- इसके अलावा ई-मित्र के माध्यम से राज्य सरकार की 600 से अधिक सेवाएं आमजन को ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं।
- ई-गवर्नेंस श्रेणी में ही राज्य सरकार के कार्मिकों के लिये बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म राजकाज को स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया है।
- हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्यों के लिये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। वहीं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आईटी के माध्यम से प्रदेश को एक पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
- राज्य सरकार की ओर से आईटी आयुक्त आशीष गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी अधिकारी (आईटी) राजेश कुमार सैनी एवं प्रोजेक्ट ऑफिसर नेहा चौधरी ने पुरस्कार ग्रहण किया।

नोट :

पुलिस आधुनिकीकरण योजना की क्रियान्विति एवं प्रगति की समीक्षा के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन

चर्चा में क्यों ?

21 दिसंबर, 2022 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में पुलिस आधुनिकीकरण योजना की क्रियान्विति एवं प्रगति की समीक्षा के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस समिति में चार सदस्य व एक संयोजक होंगे, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव-वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव-आयोजना, महानिदेशक पुलिस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, स्टेट क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो सदस्य व संयुक्त शासन सचिव-गृह (पुलिस) संयोजक रहेंगे।
- यह समिति स्थायी होगी एवं समिति का प्रशासनिक विभाग गृह विभाग होगा।

मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के लिये 28.23 करोड़ रुपए की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

21 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के समुचित आवास के लिये 'मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना'के लिये 28 करोड़ 23 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिये विभागीय भवन निर्मित होने तक गृहों का संचालन उपलब्ध राजकीय भवनों में तथा राजकीय भवनों की अनुपलब्धता की स्थिति में किराए के भवनों में किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों का वृहद् निर्माण कार्य किये जाने के साथ-साथ आवासीय भवनों के लिये कपड़े, बिस्तर एवं खाद्य सामग्री का क्रय किया जाएगा। इस राशि का उपयोग किराया, कर दर, रायल्टियाँ एवं सहायतार्थ अनुदान में भी किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में 75-75 आवासीय क्षमता के 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों को स्थापित किये जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के क्रम में यह वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल-2023 के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

21 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के खेल एवं युवा मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री अशोक चांदना ने जयपुर के शासन सचिवालय में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल-2023 के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अगले वर्ष 26 जनवरी से प्रस्तावित शहरी ओलंपिक खेलों के लिये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल जैसा अनूठा आयोजन करने के साथ राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने वाला पहला राज्य है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। राजस्थान खेल क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिये निरंतर एक 'ट्रेंड सेटर'के रूप में उभर रहा है।
- उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की अभूतपूर्व सफलता के बाद शहरों में भी इन खेलों को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

नोट :

- उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल-2023 का आयोजन आगामी जनवरी माह में प्रस्तावित है।
- राज्य के सभी 240 नगरीय निकायों में इन खेलों का आयोजन होगा, जिसमें 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद एवं 194 नगर पालिकाएँ शामिल हैं। इसके लिये निकायवार कुल 628 क्लस्टर्स का निर्माण किया गया है।
- नगर निगम एवं नगर परिषद में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रति 20-25 हज़ार की आबादी पर एक क्लस्टर बनाया गया है। हालाँकि नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं जयपुर हैरिटेज में जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति 30-35 हज़ार की जनसंख्या पर एक क्लस्टर बनाया गया है। वहीं, प्रत्येक नगर पालिका को एक इकाई मानते हुए एक क्लस्टर के रुप में माना गया है।
- खेल राज्यमंत्री ने बताया कि शहरी ओलंपिक के तहत 7 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। इनमें कबड्डी (बालक एवं बालिका वर्ग), टेनिस बॉल क्रिकेट (बालक एवं बालिका वर्ग), खो-खो (बालिका वर्ग), वॉलीबॉल (बालक एवं बालिका वर्ग), एथलेटिक्स (100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर), फुटबॉल (बालक एवं बालिका वर्ग) एवं बास्केटबॉल (बालक एवं बालिका वर्ग) में आयोजित किये जाएंगे। प्रतियोगिताओं का आयोजन नगर निकाय, ज़िला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा।
- खेल एवं युवा मामले विभाग के शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि इन खेलों में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। खिलाड़ियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल rajasthan.gov.in के माध्यम से 21 जनवरी तक किया जा सकता है। पंजीयन व्यक्तिगत अथवा सामूहिक श्रेणियों में करवाया जा सकता है।
- इन खेलों का आयोजन खेल विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से करवाया जाएगा।
- शासन सचिव ने बताया कि प्रत्येक नगर निगम में क्लस्टरों का विभाजन ज़ोनवार होगा जिसका नियंत्रण अधिकारी उपायुक्त-ज़ोन होगा तथा सभी नगरीय निकाय खेलों के आयोजन के लिये निकायवार स्थल का चुनाव करेंगे।

लोक संस्कृति के अनूठे पर्व 'शिल्पग्राम' उत्सव का हुआ आगाज

चर्चा में क्यों ?

21 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की झीलों की नगरी नाम से मशहूर उदयपुर में लोक संस्कृति के अनूठे पर्व 'शिल्पग्राम उत्सव' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम के आरंभ में राज्यपाल ने संगम सभागार में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बेणेश्वर धाम के संत मावजी महाराज के चोपड़ों में समाहित चित्रों का छायांकन कर प्रलेखन किए गये चित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
- राज्यपाल ने बताया कि उदयपुर का यह शिल्पग्राम देशभर में विख्यात है। यहाँ पर राजस्थान, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की ग्रामीण और स्वदेशी संस्कृति एक साथ अनुभूत की जा सकती है। इन सभी राज्यों के विभिन्न जातीय समुदायों की संस्कृति, उनकी जीवनशैली और परंपराओं को यहाँ झोपड़ियों में दर्शाया गया है।
- शिल्पग्राम उत्सव में 400 शिल्पकार और 700 लोक कलाकार भाग ले रहे हैं। शिल्पग्राम में बेणेश्वर धाम के संत मावजी महाराज के चोपड़ों में समाहित चित्रों का छायांकन कर प्रलेखन किया गया है, जो देश की धरोहर है।
- राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के तमाशा कलाकार व रंगकर्मी दिलिप कुमार भट्ट तथा अहमदाबाद के संस्कृति कर्मी तथा जनजाति कला के उन्नयन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉ. भगवान दास पटेल को पद्मभूषण डॉ. कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया।
- शिल्पग्राम उत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्य रंगमंच पर 'समागम'के आयोजन के अंतर्गत 9 राज्यों के सवा दो सौ कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरूआत प्रोलोग से हुई जिसमें दीपों से उत्सव का प्रकाश फैलाया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के श्रीखोल नृत्य से कार्यक्रम की शुरूआत हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर रॉफ, असम का बोडई शिखला, उड़ीसा को गोटीपुआ, महाराष्ट्र का लावणी, गोवा का समई, झारखंड का छऊ गुजरात का डांग और पंजाब के भांगड़े की प्रस्तुतियाँ सम्मोहक रहीं।

नोट :

जल जीवन मिशन के तहत 1055 करोड़ 99 लाख रुपए की 104 संशोधित लघु पेयजल योजनाओं (ओटीएमपी) को स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

22 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड (आरडब्ल्यूएसएसएमबी) की वित्त समिति की बैठक में विभाग ने 1055 करोड़ 99 लाख रुपए की 104 संशोधित लघु पेयजल योजनाओं (ओटीएमपी) को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तय लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इन लघु पेयजल योजनाओं (ओटीएमपी) के माध्यम से प्रदेश में 1 लाख 18 हज़ार 588 हर घर जल कनेक्शन दिये जाएंगे।
- बैठक में जोधपुर ज़िले की 183 करोड़ 83 लाख रुपए की तिंवरी-मथानिया-ओसियाँ-बावड़ी-भोपालगढ़ जलापूर्ति परियोजना की निविदा को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 131 करोड़ 97 लाख रुपए की बाड़मेर एवं रामसर तहसील को नर्मदा आधारित जलापूर्ति परियोजना की निविदा को भी स्वीकृति दी गई। परियोजना के तहत इन दोनों तहसीलों के 217 गाँवों में जल कनेक्शन, स्वच्छ जलाशयों के निर्माण एवं पंपिंग स्टेशन सहित अन्य कार्य भी किये जाएंगे।
- बैठक में बारां ज़िले के छबड़ा एवं छीपा बडौद क्षेत्र के करीब 20 से अधिक गाँवों को ल्हासी डेम से पेयजल पहुँचाने के लिये 34 करोड़ 34 लाख रुपए की परियोजना की निविदा को मंजूरी दी गई। इसके तहत उच्च जलाशय, पंपिंग स्टेशन, जल कनेक्शन जैसे कार्य होंगे।
- इसके अलावा उदयपुर ज़िले की बडगाँव पंचायत समिति के 11 गाँवों में जल कनेक्शन देने के लिये 11 करोड़ 79 लाख रुपए की परियोजना की निविदा स्वीकृत की गई।
- जोधपुर ज़िले की भोपालगढ़ पंचायत समिति के मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के गाँवों में जल कनेक्शन एवं पाइप लाइन जैसे कार्यों के लिये 6 करोड़ 5 लाख रुपए की निविदा को भी मंजूरी दी गई।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किया राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

23 दिसंबर, 2022 को राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र परिसर स्थित शिल्पग्राम में राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हस्तनिर्मित आकर्षक उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन का यह मेला 23 दिसंबर से 1 जनवरी, 2023 तक चलेगा, जिसमें जयपुर राईट अपने मनपसंद उत्पादों की खरीद कर सकेंगे।
- इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के द्वारा तैयार उत्पाद बेहतरीन कारीगरी और हुनर का उदाहरण हैं तथा राज्य सरकार की महिला सशक्तीकरण की मुहिम में जयपुर राईट्स भी इनके उत्पादों को खरीद कर योगदान दे सकते हैं।
- राज्य सरकार आईएम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं जैसी योजनाओं से महिलाओं को बैंकों द्वारा अनुदानित ऋण प्रदान कर उन्हें उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही है।
- ममता भूपेश ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राष्ट्रीय अमृता हाट के माध्यम से जहाँ उनके उत्पादों की बिक्री के लिये बाज़ार उपलब्ध करवाया जाता है, वहीं जयपुरवासियों को एक ही जगह प्रदेशभर के हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं खरीदारी का अवसर मिलता है।
- विदित है कि राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।

नोट :

- राष्ट्रीय अमृता हाट में राजस्थान राज्य के सभी ज़िलों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जा रही है। इसमें 140 से ज़्यादा स्टॉल्स पर महिलाओं को बेहतरीन कारीगरी के उत्पादों को बेचने का अवसर मिला है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, कशीदाकारी, लाख की चूड़ियाँ, पेपरमेशी आईटम, सलवार-सूट, टेराकोटा, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, चिकन एवं जरी वर्क, काँच एवं पेच वर्क, सभी के पसंदीदा अचार, मुरब्बा, मसाले एवं अन्य हस्तनिर्मित आकर्षक उत्पाद उपलब्ध हैं।

श्रीगंगानगर ज़िले में राज सखी कैफे का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

23 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िला प्रभारी एवं आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु राज सखी कैफे का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर ज़िला कलक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि महिलाएँ समूह में जुड़ कर पीएनबी आरसेटी से ट्रेनिंग लेकर अपने गाँव में स्वरोज़गार शुरू कर हस्तनिर्मित उत्पाद बना रही हैं। इन समूह की सदस्यों के आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका द्वारा राज सखी कैफे की शुरुआत की गई है।
- उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालयों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार खाद्य पदार्थों को प्रशिक्षण और बैठक के दौरान ऑर्डर के लिये प्रेरित किया जाएगा, ताकि महिलाओं का आजीविका में बढ़ोतरी हो सके।
- राजीविका ज़िला परियोजना प्रबंधक डॉ. दीपाली शर्मा ने इस पहल को इलाके के लिये शुभ करार देते हुए बताया कि आमजन भी राजीविका राज सखी कैफे में आकर इन महिलाओं द्वारा बनाए खाद्य उत्पादों को खाकर इनका हौसला बढ़ाएँ। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य उत्पाद चाय, कचोरी, समोसा, कुकीज, भेलपूरी, सैंडविच, वेज बर्गर, पकौड़ा इत्यादि विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे।

बाड़मेर-जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गेल इंडिया करेगी खनिज तेल व प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन

चर्चा में क्यों ?

25 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के बाड़मेर-जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बाड़मेर-जैसलमेर के क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के एक्सप्लोरेशन के लिये गेल इंडिया को 3 साल प्लस 9 माह के लिये ब्लॉक आवंटित किया गया है। गेल इंडिया को ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत सप्तम चक्र में यह ब्लॉक आवंटित किया गया है।
- उन्होंने बताया कि यह पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय की अनुशंसा पर जारी किया गया है। गेल इंडिया द्वारा इस क्षेत्र में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जाएगी।
- विदित है कि देश में ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। वर्तमान में प्रदेश में ओएनजीसी व ऑयल इंडिया द्वारा बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पेट्रोलियम व गैस का उत्पादन किया जा रहा है। इसके लिये ओएनजीसी को 9 व ऑयल इंडिया को 2 लाइसेंस दिये हुए हैं।
- इसके अलावा राज्य में 16 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी कर एक्सप्लोरेशन कार्य किया जा रहा है, जिसमें वेदांता को 9 लाइसेंस, ऑयल इंडिया को 5, ओएनजीसी और गेल इंडिया को 1-1 पीईएल जारी है। एक्सप्लोरेशन का कार्य बाड़मेर-जैसलमेर के साथ ही बीकानेर और श्रीगंगानगर क्षेत्र में भी हो रहा है।

नोट :

- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि गेल गैस को बाड़मेर व जैसलमेर में आरजे-ओएनएचपी-2021/1 ब्लॉक का आवंटन किया गया है। इस क्षेत्र में गेल इंडिया द्वारा खनिज क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, कोल बेड मिथेन सीबीएम और शैल गैस की खोज व उत्पादन किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि गेल द्वारा प्रति छह माह में ऑपरेशन, बोरिंग व प्रोडक्शन की जानकारी आवश्यक रूप से दी जाएगी। इसी तरह से एक्सप्लोरेशन के दौरान अगर अन्य खनिज मिलता है तो उससे भी तत्काल अवगत कराएगी। गेल द्वारा एक्सप्लोरेशन के दौरान आर्मी से जुड़े क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन, सर्वे और डिगिंग गतिविधियाँ नहीं की जा सकेंगी।
- खनिज तेल और गैस की उत्पादकता बढ़ने से प्रदेश में निवेश, रोज़गार व राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में प्रदेश में लगभग एक लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल व करीब 41 से 44 लाख घनमीटर गैस का उत्पादन हो रहा है।

16 राज्यमार्गों के निर्माण के लिये 4279.70 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

26 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मज़बूत सड़क तंत्र विकसित करने की दिशा के क्रम में प्रदेश के 16 राज्यमार्गों (14 राज्य राजमार्ग एवं 02 एम.डी.आर. सड़क) के निर्माण के लिये 70 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बाह्य सहायता जैसे विश्व बैंक एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक की वित्तीय सहायता द्वारा राज्य राजमार्गों का विकास करवाया जा रहा है। इसी क्रम में एशियन डेवलपमेंट बैंक ट्रेंच-प्रथम के अंतर्गत 16 राज्य राजमार्गों के निर्माण हेतु पूर्व में 36 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसको संशोधित करते हुए अब 4279.70 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृति जारी की गई है।
- उन्होंने बताया कि उक्त कार्यों पर अब तक 40 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। इसमें 4 सड़कों का निर्माण इंजीनियरिंग-प्रोक्यूरमेंट-कंस्ट्रक्शन मोड (ईपीसी) के द्वारा तथा 12 सड़कों का निर्माण वार्षिकी आधार पर करवाया गया है, जिसमें निर्माण कार्य के दौरान ईपीसी कार्यों हेतु 100 प्रतिशत राशि तथा वार्षिकी आधारित कार्यों हेतु 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के राज्यमार्गों के विकास हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत पीपीपी खंड गठित किया हुआ है, जिसके द्वारा पीपीपी/ई.पी.सी. मोड पर स्टेट हाईवे के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। अब तक 3577 किमी. लंबाई के 58 स्टेट हाईवे के विकास के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनकी स्वीकृत लागत 11604 करोड़ रुपए है।
- प्रदेश के स्वीकृत 58 स्टेट हाईवे में से अब तक 24 स्टेट हाईवे का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, 14 सड़कों के कार्य प्रगतिरत है, 5 सड़कों के अनुबंध संपादित किये जा चुके हैं, 7 सड़कों के एल.ओ.ए. जारी/प्रक्रियाधीन हैं एवं 8 सड़कों के निविदा प्रक्रियाधीन हैं।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

26 दिसंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा, जयपुर में राज्य विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों व सचिवों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा में होगा।

प्रमुख बिंदु

- राज्य विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने बताया कि यह 83वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मलेन है, जो 11 और 12 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में होगा। विधानसभाओं के सचिवों की 59वीं कॉन्फ्रेंस भी 10 जनवरी को होगी।
- उन्होंने बताया कि इस सम्मलेन में विभिन्न बिन्दुओं पर सार्थक चर्चा होगी तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और पूर्व विधानसभा सचिवों को भी इस सम्मलेन में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

नोट :

- मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बताया कि सम्मलेन की सभी व्यवस्थाएँ पुख्ता रहेंगी और सभी अधिकारियों को इस संबंध में सौंपे गए दायित्वों को निष्ठा से किये जाने के निर्देश दिये।
- विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि राजस्थान को इस सम्मलेन का मौका 11 वर्ष बाद मिला है। इससे पहले राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का सम्मलेन वर्ष 2011 में आयोजित हुआ था।

'राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस' योजना के लिये 65 करोड़ रुपए मंज़ूर

चर्चा में क्यों ?

27 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं के विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सपने को पूरा करने के क्रम में 'राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस' योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 65 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में नि:शुल्क अध्ययन के लिये पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की जयंती (20 अगस्त, 2021) पर 'राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस' योजना शुरू की थी। इसमें प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को विदेश में नि:शुल्क शिक्षा दिलाने का प्रावधान है।
- इस योजना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी सहित विश्व की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़/इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का अवसर दिया जा रहा है।
- 'राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस' योजना में 8 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें 25 लाख रुपए तक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें छात्राओं के लिये 30 प्रतिशत सीट आरक्षित है। इसके लिये विद्यार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने राजस्थान डीआईपीआर को दिया इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्यूनिकेशन अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

27 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजस्थान सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन एवं लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिये इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्यूनिकेशन अवार्ड प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक अरुण जोशी ने पीआरएसआई द्वारा भोपाल में आयोजित 44वें वार्षिक अधिवेशन में यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- उल्लेखनीय है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सभी 33 ज़िलों मे वाट्सएप ग्रुप बनाने के साथ ही राज्य की सभी ग्राम पंचायतों एवं वार्ड स्तर पर वाट्सएप ग्रुप बनाकर लगभग 20 लाख लोगों को जोड़ा गया है, जिन्हें प्रतिदिन मोबाइल फोन पर प्रचार-प्रसार सामग्री भिजवाई जा रही है।
- राजकीय योजनाओं की सूचना आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सूचना ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन तथा सुजस आवाज़ (पॉडकास्ट) जैसे नवाचार किये गए हैं, जिनसे प्रतिदिन के समाचारों, लाभार्थियों के साक्षात्कार एवं महत्त्वपूर्ण राजकीय निर्णयों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।
- इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सुजस मोबाइल एप भी आरंभ किया गया है जिसमें मोबाइल पर विभाग के सभी प्रेस नोट, विशेष लेख, सफलता की कहानियाँ, महत्त्वपूर्ण छायाचित्र, ई-बुलेटिन, वीडियो बुलेटिन, सुजस आवाज़ एवं कल्याणकारी योजना के लाइव कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं, जिसे आमजन विशेषकर युवावर्ग द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है।

नोट :

प्रदेश में 'स्टेट-ऑफ-द-आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर'तथा 'ओपन जिम'स्थापित करने के लिये 31 करोड़ 50 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान

चर्चा में क्यों ?

28 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खिलाड़ियों को अभ्यास तथा प्रशिक्षण के लिये विश्व स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के क्रम में 'स्टेट-ऑफ-द-आर्ट जिम एंड 'फिटनेस सेंटर'तथा 'ओपन जिम'स्थापित करने के लिये 31 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर तथा सभी संभागीय मुख्यालयों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिम एंड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा, प्रदेश के सभी ज़िला मुख्यालयों पर ओपन जिम की स्थापना की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 2022-23 के बजट में सभी संभागों पर स्टेट-ऑफ-द-आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ज़िला मुख्यालयों पर ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी।

जोधपुर का कागल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत

चर्चा में क्यों ?

28 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर ज़िले की ग्राम पंचायत कागल पीपाड़ शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की इस मंज़ूरी से ग्राम पंचायत कागल के साथ आसपास के गाँवों के विद्यार्थियों विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये गाँव से दूर रतकुडिया अथवा भुंडाना गाँव नहीं जाना पड़ेगा।
- गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2018 की तुलना में राज्य में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा है।
- इस कारण राजकीय स्कूलों को निरंतर अपग्रेड करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य के समस्त 3 हज़ार 820 सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की थी।
- इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिये ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एवं यथा आवश्यकता क्रमोन्नत किये जाने की भी घोषणा की थी।

10वाँ अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह

चर्चा में क्यों ?

29 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह-2022 में अनेक आदिवासी प्रतिभाओं को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह-2022 में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध है। इसके लिये सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्र के हित को ध्यान में रखकर ही योजनाएँ भी तैयार की जा रही हैं।

नोट :

- उन्होंने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से हर परिवार को दस लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है जो देशभर में पहला उदाहरण है। प्रदेश में अनुप्रति योजना के माध्यम से बीस हज़ार छात्रों को कोचिंग कारवाई जा रही है। इसी प्रकार से उड़ान योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं को हर माह 12 सेनेट्री नेपकिन उपलब्ध करवा रही है।
- अशोक गहलोत ने बताया कि आज विश्व में अंग्रेजी की अहमियत को देखते हुए प्रदेश में जगह-जगह महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं जिससे अब निर्धन परिवारों के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध हो रही है।
- इस समारोह में मुख्यमंत्री ने उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को 'श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार' से सम्मानित किया। दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा को 'नाना भाई खांट शिक्षक गौरव पुरस्कार' से, डॉ. किरण मीणा को 'आदिकवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार', सीडीपीओ दीपिका मीणा को 'मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार', पवन पुत्र नि:शुल्क कोचिंग संस्था के संचालक रणवीर ठोलिया को 'वीर शहीद नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार', डॉ. सुनील मीणा को 'वीर बालक एकलव्य पुरस्कार', राज कलासुआ को 'शहीद जनजाति वीर बाला कालीबाई पुरस्कार' तथा दृष्टिहीन क्रिकेट में अपना लोहा मनवाने वाले ललित मीणा को 'धनुर्धर श्री लिंबाराम पुरस्कार' से सम्मानित किया।

खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपी अंतिम रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

30 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिये गठित खेमराज कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार द्वारा कमेटी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण करवाकर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। कमेटी द्वारा पूर्व में अपनी अंतरिम रिपोर्ट 2 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत की गई थी, जिसकी क्रियान्विति की जा चुकी है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति में खेमराज चौधरी (सेवानिवृत्त आई.ए.एस.) की अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था।

नोट :